



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1932 (श0)  
(सं0 पटना 361) पटना, शुक्रवार, 11 जून 2010

सं0 डी0टी0डी0/डी02-03/08-720

उद्योग विभाग

संकल्प

18 मई 2010

विषय:—औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में किए गए मध्यावधि समीक्षा के आलोक में औद्योगिक इकाइयों को पूँजीगत अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में औद्योगिकीकरण की दिशा में तीव्रता लाने तथा नए पूँजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 लागू की गयी है, जो दिनांक 01 अप्रैल 2006 से अगले 5 (पाँच) वर्षों तक अर्थात् दिनांक 31 मार्च 2011 तक प्रभावी है। उपर्युक्त नीति में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने हेतु पूँजीगत अनुदान दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में नीति में मध्यावधि समीक्षा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत उपर्युक्त नीति की मध्यावधि समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान नई औद्योगिक इकाइयों को पूँजीगत अनुदान देने का अनुशंसा की गई। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में पूँजीगत अनुदान संबंधी निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं;

(क) नई लघु औद्योगिक इकाइयों को प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गए पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) पूँजीगत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 35.00 (पैंतीस) लाख रुपये होगी।

(ख) नई मध्यम एवं वृहत औद्योगिक इकाइयों को प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गए पूँजी निवेश का 10 (दस) प्रतिशत पूँजीगत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 (एक) करोड़ रु0 होगी।

(ग) पूँजीगत अनुदान इस आदेश निर्गत की तिथि के बाद उद्योगों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गए पूँजी निवेश पर ही लागू होगा तथा यह सुविधा संबंधित औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त ही देय होगी। उपर्युक्त सुविधा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की अवशेष अवधि, अर्थात् 31 मार्च 2011 तक किए गए निवेश पर ही देय होगी।

(घ) चूँकि खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की इकाइयों को खाद्य प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, अतः उन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान देय नहीं होगा।

3. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को पूँजीगत अनुदान दिए जाने संबंधी उपर्युक्त कंडिका-2(क) ख) (ग) एवं (घ) वर्तमान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका-2 (xiv) स्वरूप जोड़ा जाता है, जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में आदेश निर्गत की तिथि से अंश माना जाएगा तथा इस नीति की सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

‘लघु’, ‘मध्यम’ एवं ‘वृहत्’ औद्योगिक इकाइयों का तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाइयों से है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर तय की गई सीमा तक पूँजी निवेश किया गया हो।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी सूचना सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को दी जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 361-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>